सम्पादक के नाम

वेलकम राष्ट्रवादी महंगाई

जैसा हम सोच रहे थे वैसा ही हुआ है , चुनाव निपटते ही आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ना शुरू हो गई है। गुजरात की कोऑपरेटिव संस्था अमूल ने दूध के दामों में प्रति लीटर 2 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। इससे पहले इतनी बड़ी वृद्धि पहले कभी नहीं देखी गयी इसका फायदा लेकर सभी शहरों में दाम बढ़ा दिए जाएंगे.....

वैसे लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं अब यह सिलसिला रुकने वाला नही है धीरे धीरे करके यह दाम 4 से 5 रुपए बढ़ा दिए जाएंगे.....जिसका सीधा असर खाद्य सामग्री की कीमतों पर पड़ेगा इसके अलावा आप आगामी दिनों में गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी महंगा होना निश्चित ही समझिए.....

इंश्योरेंस रेग्युलेट्री एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मौजूदा वित्त वर्ष में एक हजार सीसी से कम की कारों के लिए मोटर थर्ड पार्टी (टीपी) की प्रीमियम दर को बढ़ाकर 2,120 किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि 2019-20 के वित्त वर्ष में यह 1,850 रुपए है, वहीं, एक हजार सीसी से 1500 सीसी के बीच की गाडियों के प्रीमियम को 2836 रुपए से बढ़ाकर 3300 किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है।

हालांकि, 1500 सीसी से ऊपर की लग्जरी गाड़ियां के टीपी प्रीमियम में किसी तरह के फेरबदल की बात नही की गयी है आखिर लग्जरी गाड़ी रखने वालों ने चुनावी चन्दा दिया है तो उन्हें इतनी छूट तो दी जानी.... चैये की नई चैये.....

जब एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि मध्यम वर्ग पीठ पर इतने कोड़े झेलने के बाद भी शिकायत नही कर रहा है तो दो चार कोड़े तो ओर हँसी खुशी झेल लेगा ... एक खबर तो हम आपको बताना भूल ही गए पिछले कुछ दिनों से दाल की बढ़ती कीमतों से जनता बेहाल हो रही है.....थोक में दालों के दामों में चार से पाच रुपये का इजाफा हुआ है, लेकिन रिटेल बाजार में तो सीधे दस से पंद्रह रुपये की बढ़ोतरी हो गई है, चुनाव की भागमभाग में दालों की आवक कम ही रह गई है, व्यापारी बता रहे हैं कि दलहन की खेती में किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है जिस कारण इसकी बुआई कम हुई है। यही कारण है कि दाम बढ़े हैं.....

हमे तो लगता है किसान साफ झूठ बोल रहा है जब मोदी जी ने समर्थन मूल्य को दोगुना कर दिया है तो यह बात कैसे मानी जा सकती है भला ?.....

जब किसान खुश हैं जवान भी खुश हैं मीडिया भी खुश हैं .....नारे लगा रहा है कि 'आयेगा तो मोदी ही' ..... 'मोदी है तो मुमकिन है'..... तो क्यो परवाह करे आने दीजिए तो इस ससुरी 'महंगाई डायन' को।.....

- गिरीश मालवीय

माफी चाहता हूं कि मैने कुछ ज्यादा ही चाहा

चाहा कि देश मे रोजगार के अवसर बढ़ें,पढ़े लिखे लोग डिग्रियां लेकर पकौड़ा और पंचर की दुकान के सपने न देखें, बल्कि वो बनें जिसके लिए उन्होंने डिग्रियां ली हैं, स्कूल कालेज स्वास्थय सुविधाओं मे बढ़ोतरी हों और सबको सुलभ हों, किसान मजदूर खुशहाल हो, देश पर कर्ज कम हो, आतंकवादी कार्यवाही मे सैनिकों की शहादत पर लगाम लगे, देश लूट कर भागने वाले पकड़े जाएं, काला धन वापस आए और देश के विकास मे लगे, सांप्रदायिक सदभाव बना रहे, दलितों पर अत्याचार कम हों, अपराध कम हों, महिलाओं और बच्चे सुरक्षित रहें, बलात्कार की घटनाओं पर लगाम लगे, महंगाई कम हो, पेट्रोल डीजल गैस के दामों मे कमी आए, वायु जल नदियों का प्रदूषण रोका जाए, देश तरक्की करे !

माफ करें कुछ ज्यादा तो नहीं चाहा ? लेकिन ये चाहत अभी भी बरकरार है दोस्तों ! लड़ाई जारी रहेगी अपनी !

- महेंद्र सिंह

आप गोडसे क्यों बनना चाहते हैं!

इसलिए कि-

- गोडसे ने स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया!
- गोडसे ने आज़ादी के लिए गोलियां खाई!
- या लम्बे समय तक आज़ादी के लिए जेल में रहे!
- या फिर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और अछूतो, आदिवासियों के लिए कोई आंदोलन किया या कोई जागरूकता अभियान चलाया !
- या फिर महिलाओं के उत्थान के लिए संघर्ष किया!

कोई विद्यालय खोला जिससे महिलाएं या फिर किसी वंचित तबके का भला हुआ।

- या फिर उन्होंने मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए कोई आंदोलन किया!
- या फिर विकास का उनके पास कोई खाका था जो देश हित के लिए आवश्यक था!
- या फिर गोडसे ने किसानों के लिए ही कुछ संघर्ष किया,उनके ऊपर लगने वाले लगान या अन्य कर के खिलाफ कोई झंडा बुलंद किया!
- या देश मे कोई ऐसी संस्थान की नींव डाली जिसने कभी भी देश का कोई हित किया!
- या फिर जाति उन्मूलन की कोई लड़ाई लड़ी!

इनमें से ऐसा कौन सा योगदान रहा जिसके लिए आप या तो गोडसे बनना चाहते हैं या फिर गोडसे जैसों की फौज तैयार करना चाहते हैं !

आप गांधी से नाराज़ हैं या उनकी भूमिका को लेकर सहमत नही है तो कौन कहता है कि आप गांधी की तख्ती लेकर बैठिए।

हां आप किताबों के बीच जाइए और उनको एवं उनसे सहमति रखने वालों को तर्कों से खारिज करिए। ये कौन सा रास्ता है कि आप उनके पुतले पर गोली चलाएंगे! या फिर उन पर गोली चलाने वाले को महिमामंडित करेंगे!

आपके अंदर जो देशभक्ति उबाल मार रही है उसको देखकर तो यही लगता है कि आप अगर उस समय पैदा हुए होते तो कोई महान क्रांतिकारी हुए होते ! लेकिन अफसोस कि यह देश आपका ऋणी नही हो सका! लेकिन सच कह रहा हूं कि अभी भी इस राष्ट्र पर एक एहसान तो कर ही सकते हैं कि यह देश चाहे जैसे भी आपको मिला उसके उत्थान में अगर सहयोग नही कर सकते तो ना सही उसको पतन के कुएं में तो मत धकेलिए!

और हां किसी को धर्म का मोह सता रहा हो तो आपको चेता रहा हूं कि याद रखिए हिन्दू धर्म को इन जैसे लोगों ने ही कमजोर किया है और अपमानित किया है!

- अभिषेक प्रकाश

गंगा साफ हो जायेगी तो अधिकारियों-राजनेताओं की जेब कैसे होगी मालामाल

तमाम सरकारी संस्थान जो आज नदी की सफाई कर रहे हैं, वही हैं जो 1986 से इसकी सफाई करते आ रहे हैं और मालामाल होते जा रहे हैं। आखिर गंगा सा ? हो जायेगी तो माल कहाँ से आएगा?

महेंद्र पाण्डेय, वरिष्ठ लेखक

एमसी मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 1985 में गंगा के प्रदूषण से सम्बंधित याचिका दायर की थी। वर्ष 2014 तक सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका पर अनगिनत फैसले और निर्देश दिए, पर गंगा और प्रदूषित होती रही। वर्ष 2014 में गंगा प्रदूषण से सम्बंधित सभी याचिकाएं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में स्थानांतरित कर दी गयीं। इस दौरान एनजीटी ने भी अनगिनत निर्देश और फैसले इस मामले में दिए, पर गंगा प्रदूषित होती रही।

यही नहीं जिन प्रान्तों से होकर गंगा बहती है, लगभग सभी प्रान्तों के उच्च न्यायालयों में भी गंगा प्रदूषण से सम्बंधित अनेक याचिकाएं दायर की गयीं, निर्देश और फैसले वहां से भी आते रहे पर गंगा पहले से अधिक प्रदूषित होती रही। वर्ष 2014 से नमामि गंगे का शोर भी शुरू हो गया, उमा भारती 2018 में ही गंगा अविरल और निर्मल कर रही थीं, इसके बाद नितिन गडकरी ने 2019 में गंगा साफ करने का दावा किया, पर गंगा और प्रदूषित होती रही।

यह एक भद्दा मजाक इसलिए भी है क्योंकि देश की लम्बाई के सन्दर्भ में सबसे लम्बी गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी मिल गया, पर नदी का प्रदूषण बढ़ता रहा। इस नदी को एक खिलौना या कठपुतली जैसा बना दिया गया है, जिसमें अर्ध-कुम्भ को महाकुम्भ बनाने के लिए पानी छोड़ दिया जाता है और उत्सव के अंत में इसे फिर से सूखा छोड़ दिया जाता है।

कुम्भ के नाम पर इसके डूब क्षेत्र से अपनी मर्जी से छेड़छाड़ की जाती है, कहीं द्वीप बनाए जाते हैं तो कहीं पूरी तरह से समतल कर दिया जाता है, पर उस समय सभी न्यायालय चुप्पी साध लेते हैं, या फिर याचिकाकर्ता को ही सजा देने की बात करने लगते हैं। लाखों शौचालय बनाए गए, खूब दावे भी किये गए साफ-सफाई के पर हकीकत यही है कि हरेक कचरा, पूरा मल-मूत्र सभी कुछ नदी में ही पहुंच गया और नमामि गंगे की माला जपने वाले बस तारीफ के पुल बांधते रहे।

नमामि गंगे गैंग अपने आप में एक मजाक से कम नहीं है। मोदी जी ने कहा, गंगा ने मुझे बुलाया है फिर बनारस में घाटों पर ढेर सारी सीढियां बनवा दीं और गंगा आरती भव्य करा दी, उन्हें लगा कि इससे गंगा साफ हो जायेगी। उमा भारती ने जल समाधि की बात की, अविरल और निर्मल को बार बार दुहराया, लच्छेदार हिन्दी में बार-बार गंगा पर प्रवचन देती रहीं और उन्हें लगा कि गंगा साफ हो जायेगी।

नितिन गडकरी आये और गंगा में जल-पोट और क्रूज चलाना शुरू किया, उन्हें लगा कि गंगा साफ हो गयी। योगी जी तो अपने आप को भागीरथ ही समझ बैठे, जितने दिन उनकी मर्जी होगी गंगा में पानी होगा, जब पानी होगा तो वे अपनी मर्जी से इसकी धारा निश्चित करेंगे।

इन सबके बीच अनेक स्वामी/संन्यासी पता नहीं किससे और कौन सी उम्मीद लेकर लगातार अनशन/तपस्या करते रहे, कुछ ने अपने प्राण भी त्याग दिए पर गंगा ना तो निर्मल हुई और ना ही अविरल हुई। अलबत्ता निर्मल तो नहीं पर अविरल सरकारी आश्वासन जरूर मिलते रहे।

एनजीटी में माननीय आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता में प्रमुख पीठ ने 14 मई 2019 को दिए गए अपने फैसले में अनेक बातें कही हैं, जिससे पता चलता है कि 1985 से हम वहीं खड़े हैं, हालात में कोई सुधार नहीं आया है, गंगा में प्रदूषण कम करने और निरंतर बहाव को लेकर तमाम संस्थाएं बिना किसी ठोस कार्य योजना के ही काम कर रहीं है। जाहिर है जब एनजीटी को स्थिति में सुधार नहीं दिख रहा है तब नितिन गडकरी के गंगा सफाई के तमाम दावे अपने आप झूठे साबित हो जाते हैं।

इस फैसले में लिखा गया है, गंगा में एक बूंद प्रदूषण भी चिंता की बात है। नदी के संरक्षण के लिए सभी अधिकारियों का रवैया सख्त होना चाहिए। किसी भी प्रदूषण फैलाने वाले गतिविधि से प्रदूषण के निवारण के लिए एहतियात बरतने की आवश्यकता है। कितना भी आर्थिक लाभ हो, या फिर व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों को गंगा की सफाई की तुलना में प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। कोई भी व्यक्ति या संस्थान गंगा में प्रदूषण करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता है।

हरेक सम्बंधित राज्य एक विशेष प्रकोष्ठ बनायेंगे जो हरेक दिन गंगा में प्रदूषण फैलाने वाले गतिविधियों की निगरानी करेंगे। इस तरह की कार्यवाही देश की दूसरी प्रदूषित नदियों की सफाई के लिए एक सबक होगी। यह दुख की बात है कि सीपीसीबी के अनुसार देश में नदियों पर 351 प्रदूषित खंड हैं।

यह हास्यास्पद नहीं तो और क्या है, जिस मुकदमे की सुनवाई 1985 से चल रही हो उसके लिए जज साहब को कहना पड़े कि गंगा में एक बूंद प्रदूषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गंगा हो या कोई और नदी, पर्यावरण की कोई समस्या का हल तब तक नहीं निकलेगा जब तक किसी भी संस्थान को इसके लिए जिम्मेदार नहीं बनाया जाएगा। तमाम सरकारी संस्थान जो आज नदी की सफाई कर रहे हैं, वही हैं जो 1986 से इसकी सफाई करते आ रहे हैं और मालामाल होते जा रहे हैं। आखिर गंगा साफ हो जायेगी तो माल कहाँ से आएगा ?

कभी बोफोर्स घोटाले की जांच का हिस्सा थे जेटली, आज बदल गए हैं सुर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की एक रैली में दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बहाने राहुल गांधी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, आपके पिता को उनके दरबारी मिस्टर क्लीन कहते थे, लेकिन उनके जीवन का अंत भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में हुआ। लेकिन शायद प्रधानमंत्री मोदी इतिहास के उस हिस्से को भूल गए जिसमें उनके केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली बोफोर्स घोटाले की जांच के लिए बनी समिति का हिस्सा थे और उन्हें इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला था।

वरुण शैलेश

लोकसभा चुनाव 2019 का प्रचार अभियान गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए भी याद किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल सौदे में कथित तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। वहीं इस आरोप के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की एक रैली में दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बहाने राहुल गांधी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, 'आपके पिता को उनके दरबारी मिस्टर क्लीन कहते थे, लेकिन उनके जीवन का अंत भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में हुआ।' लेकिन शायद प्रधानमंत्री मोदी इतिहास के उस हिस्से को भूल गए जिसमें उनके केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली बोफोर्स घोटाले की जांच के लिए बनी समिति का हिस्सा थे और उन्हें इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला था।

अंग्रेजी की पत्रिका कारवां में छपी प्रवीण दोंती की रिपोर्ट बताती है कि 1987 में अरुण जेटली राजीव गांधी के सरकार में वित्त मंत्री रहे वीपी सिंह के करीबी हुआ करते थे। बाद में मतभेद बढ़ने के बाद वीपी सिंह ने राजीव गांधी की सरकार से इस्तीफा दे दिया था। दिसंबर 1989 में बोफोर्स घोटाले की लहर पर सवार होकर वी.पी. सिंह, जनता दल के नेतृत्व में बीजेपी-समर्थित नेशनल फ्रंट सरकार के प्रधानमंत्री बने और उस सरकार में जेटली अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बनाए गए।

रिपोर्ट आगे बताती है कि जेटली जैसे वकीलों की सेवाओं के चलते प्रधानमंत्री वी.पी। सिंह से अपेक्षा की जा रही थी कि वे बोफोर्स आरोपों की जांच को अंजाम तक पहुचाएंगे। जनवरी 1990 में, तत्कालीन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अरुण जेटली समेत प्रवर्तन निदेशालय (ED) के पूर्व निदेशक भूरे लाल और सीबीआई के डिप्टी इंस्पेक्टर-जनरल एम.के. माधवन का एक जांच दल जांच-पड़ताल के सिलसिले में स्विट्जरलैंड और स्वीडन गया।

मगर आठ महीने बाद वही 'ढाक के तीन पात' वाली बात हो गई। उस दौरान इंडिया टुडे के एक लेख में, एक सांसद का बयान छपा. इसमें उन्होंने कहा कि अगर जांच दल ने 'विदेशों में इसी तरह अपनी जांच जारी रखी तो उसे जल्द ही प्रवासी भारतीयों का दर्जा मिल जाएगा।'

बहरहाल, 2012 में स्वीडिश पुलिस के पूर्व प्रमुख स्टेन लिंडस्ट्रोम, जिन्होंने पत्रकार चित्रा सुब्रमण्यम को बोफोर्स संबंधित अति संवेदनशील दस्तावेज मुहैया कराए थे, ने एक इंटरव्यू में स्वीडन जाने वाली उस टीम के खिलाफ दावा कि इस जांच ने 'पानी और गंदा कर दिया था।'

लिंडस्ट्रोम ने कहना था कि चित्रा सुब्रमण्यम की रिपोर्ट में पांच स्विस बैंक खातों का जिक्र था जिनमें बोफोर्स की रिश्वत जमा की गई थी। टीम ने राजीव गांधी के करीबी दोस्त, बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन का नाम भी इसमें शामिल कर दिया, जिसकी खबर डेगेंस नाइटर नामक अखबार में छपी। बच्चन द्वारा यूके कोर्ट में दायर किया गया केस जीतने के बाद, अखबार ने अपना माफीनामा छापा. बच्चन का दावा था कि भारत सरकार की तरफ से बोफोर्स लेनदेन के मामले में सीधे-सीधे जुड़े लोगों की सूचना पर विश्वास करना भ्रमित करने वाला है। बोफोर्स मामले पर रिपोर्ट करने वाली चित्रा सुब्रमण्यम अब अरुण जेटली पर कहती हैं कि, 'वे वही कर रहे थे जो उनसे राजनीतिक रूप से अपेक्षित था'

वीपी सिंह ने आरोप लगाया था कि स्वीडन की हथियार बनाने वाली कंपनी ने कथित तौर पर भारत सरकार के साथ 1.3 बिलियन डॉलर का करार करने के लिए कथित तौर पर राजीव गांधी को रिश्वत खिलाई थी। फरवरी-मार्च 2004 में मामले की सुनवाई कर रहे कोर्ट ने स्वर्गीय राजीव गांधी और इस केस में अन्य आरोपी तत्कालीन रक्षा सचिव एस. के. भटनागर को बरी कर दिया. भटनागर का 2001 में निधन हो गया था।

अरुण जेटली ने कुछ दिन पहले समाचार एजेंसी एएनआई के साथ एक इंटरव्यू में कहा, कांग्रेस का इतिहास है कि डिफेंस डील में कांग्रेस के हाथ गंदे हैं। अरुण जेटली से यह पूछा गया कि आप यह बात बोफोर्स के बारे में कह रहे हैं तो उन्होंने कहा, बोफोर्स है, एचडीडब्ल्यू है, कितनी डील्स हैं,

इसी तरह अरुण जेटली ने राफेल मामले में जांच समित गठित करने की मांग पर 2 जनवरी 2019 को संसद में कहा कि, बोफोर्स की जांच के लिए बी. शंकरानंद की अगुवाई में जेपीसी बनी थी। अब साबित हो गया है कि बोफोर्स में भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन जेपीसी ने बोफोर्स में कांग्रेस को क्लीन चिट दे दी थी। बोफोर्स घोटाले में फंसे लोग जेपीसी की मांग कर रहे हैं, ताकि मोदी सरकार पर अभी तक जो भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, जेपीसी के जरिए यह फर्जी आरोप सरकार पर लगाए जाएं। इसलिए सरकार जेपीसी की मांग को ठुकराती है.